और... एक शे'र

इलाजे दर्दे दिल तुम से मसीहा हो नहीं सकता
तुम अच्छा कर नहीं सकते मैं अच्छा हो नहीं सकता
-मुज़तर ख़ैराबादी

लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

{ गरीबों के समान विनम्र अमीर और अमीरों के समान उदार गरीब ईश्वर के प्रिय पात्र होते हैं. ■ शेख सादी }

संपादकीय

गांवों की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं चिंता का विषय

छत्तीसगढ़ के नक्सल इलाके में डेंगू का कहर बरपा हुआ है. सुकमा जिले के कोंटा क्षेत्र में मरीजों की जांच के लिए चिकित्सकों के दल को पहुंचाने के लिए हेलिकॉप्टर और नाव की मदद लेनी पड़ी. जांच दल को इलाके के सर्वेक्षण के दौरान लगभग हर घर में बुखार पीड़ित मिले. कोंटा और आसपास के क्षेत्र में डेंगू के मच्छरों के प्रकोप से न केवल ग्रामीण, बल्कि सेना के जवान भी पीड़ित हो रहे हैं. ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं-सुविधाओं की बदहाली की यह एक बानगी मात्र है. कुछ दिन पहले जारी हुए सामाजिक-आर्थिक जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक शहरीकरण की तेज रफ्तार के बावजूद देश की लगभग तीन चौथाई आबादी अभी भी गांव-कस्बों में ही रहती है. इसमें भी करीब आधी आबादी किसी-न-किसी तरह के अभाव से जूझ रही है. तमाम कार्यक्रमों और दावों के बावजूद हमारे गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता आज भी सहज सुलभ नहीं है. बाजारवाद पर केंद्रित हो चली अर्थव्यवस्था के चलते शहर तो समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे गांव आज भी हाशिए पर ही मालूम पड़ते हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय जैसी तमाम बुनियादी सुविधाओं का रुख शहरों की ओर हो रहा है, जबकि बुनियादी सुविधाओं से गांव महरूम बने हुए हैं. दरअसल, हमारी सरकारों की प्राथमिकता में गांव शुरू से ही दोयम स्थान पर रहे हैं और मौजूदा सरकार भी स्मार्ट सिटी के नाम पर शहरों को ही सजाने-संवारने की बात कर रही है. 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' जैसी प्रतीकात्मक पहल के जरिए यह संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है कि सरकार गांवों को लेकर भी चिंतित है, लेकिन क्या कुछ चुनिंदा गांवों को चमका कर समूचे ग्रामीण भारत का विकास किया जा सकता है? देश में कई सामाजिक, राजनैतिक, भौगोलिक और प्रशासनिक कारणों से स्वास्थ्य सेवा एक उपेक्षित क्षेत्र रहा है. अधिकांश ग्रामीण भागों में(कई शहरों की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं) स्वास्थ्य के लिए जरूरी बुनियादी वातावरण जैसे सुरक्षित पानी, अच्छा पोषण और मल-मूत्र आदि के सुरक्षित निपटारे का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है. इसलिए संक्रामक और कुपोषणजन्य बीमारियों का प्रकोप भी बना रहता है. हमारे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का विकास बहुत ही असमान रहा है. शहरी लोगों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और गांव उपेक्षित रह जाते हैं. हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हालत बेहद खराब है. उनकी संख्या भी जनसंख्या के मुकाबले पर्याप्त नहीं है. दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकारी बजट बहुत ही कम होता है.ज्यादातर देशों में स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं, परंतु भारत में अपर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की जगह निजी स्वास्थ्य सेवाओं ने भरी है जिनका एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना है. हमारे यहां चिकित्सा और स्वास्थ्य के पुराने और पारंपरिक तरीकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है. इलाज के पारंपरिक तरीकों को ध्यान से आगे बढ़ाना चाहिए, जैसा कि चीन में किया गया है. ये उतने महंगे भी नहीं होते. ऐसा करके लोगों के सांस्कृतिक विश्वास को सहेजते हुए ग्रामीण भारत को सस्ता इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है. ■■

अंधेरे से लड़ने की बड़ी चुनौती

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

मंथन-चिंतन-आत्मावलोकन सचमुच आवश्यक है, सत्ता और संगठन के लिए यह प्रक्रिया अपरिहार्य है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री तथा वरिष्ठ मंत्री 2 सितंबर से तीन दिन तक मंथन करने वाले हैं. वर्षों के संघर्ष के बाद बैसाखियों के बिना संघ-भाजपा को सत्ता का सिंहासन मिला है. संघ के प्रचारकों और स्वयंसेवकों द्वारा बनाए गए पहले राजनीतिक संगठन का नाम भारतीय जनसंघ था और चुनाव चिह्न 'दीपक' था. 1977 में प्रतिपक्ष की एकजुटता के लिए भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हो गया. लेकिन यह बेमेल गठबंधन तीन वर्ष के शैशव काल में ही बिखर गया. राजनीतिक दलदल से बाहर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने 'कमल' की तरह खिलते रहने का लक्ष्य बनाया. अब यह 'कमल' उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों के साथ राष्ट्रीय कुंड में खिला हुआ है. लेकिन इस विस्तार के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हवा-पानी और अज्ञान-अविश्वास-कुरीतियों के अंधेरे से लड़ने की चुनौतियां बढ़ गई हैं. समय के साथ संघ-भाजपा के रंग-रूप, नियम-परंपरा में बदलाव स्वाभाविक है. लेकिन संघ के समर्थक ही नहीं आलोचक भी मानते हैं कि भाजपा के नेता संघ के मूलभूत विचारों तथा उद्देश्यों से अलग नहीं हो सकते हैं. इस सप्ताह के मंथन में सत्ता सुख की सफलताओं के साथ दोनों पक्षों को 'भटकाव' के मुद्दों पर भी विचार करना है. प्रतिपक्ष के अलावा संघ के कड़े रुख के कारण सरकार ने एक दिन पहले भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को तिरोहित करने की घोषणा कर दी. आर्थिक नीतियों के अलावा सत्ता में संघ के समर्पित स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाना सही अर्थों में अपने 'बंधुओं' के साथ सलाह-मशविरे का मुद्दा है. वहीं एक मुद्दा राजनीतिक-सामाजिक ध्रुवीकरण के साथ संघ से जुड़े अन्य संगठनों के तेवरों का हो सकता है. यहां तटस्थ प्रेक्षक सवाल उठा सकते हैं कि संघ-भाजपा के नेता क्या सचमुच 'हिंदू धर्म' का 'ध्वज' उठाते हुए उत्तेजक तथा हिंसक गतिविधियों से जुड़े संगठनों और लोगों को नियंत्रित करना चाहते हैं?

कलबुर्गी के विरुद्ध अभियान छेड़कर जान से मारने की धमकियां दे दी गईं. कर्नाटक में इस विवाद पर हंगामा घटता-बढ़ता रहा.

ताजा घटना पिछले दिनों कर्नाटक के धारवाड़ नगर में प्रतिष्ठित कन्नड़ साहित्यकार एम.एम. कलबुर्गी की हत्या की है. कलबुर्गी समाज को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालने के लिए निरंतर बोलते-लिखते थे. वह आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानंद के आदर्शों के अनुसार 'मूर्ति पूजा' को भी अनावश्यक मानते थे. लेकिन भारतीय संस्कृति और जीवन-मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी. हमेशा की तरह पिछले वर्ष जून 2014 में 77 वर्षीय कलबुर्गी ने बेंगलुरु की एक संगोष्ठी में भाषण के दौरान मूर्ति पूजा की निरर्थकता की बातें भी कहीं. यह संगोष्ठी कर्नाटक विधानसभा के लिए विचाराधीन 'अंधविश्वास विरोधी विधेयक' के संबंध में थी. इसलिए स्वामी दयानंद, विवेकानंद, राजा राममोहनराय जैसे महान विचारकों के आदर्शों का उल्लेख स्वाभाविक था. कन्नड़ के ही एक अन्य वरिष्ठ साहित्यकार यू.आर.अनंतमूर्ति भी मूर्ति पूजा और अंधविश्वास पर आलोचनात्मक पुस्तक लिख चुके हैं. इस दृष्टि से कलबुर्गी ने उनका भी उल्लेख किया. लेकिन अगले ही दिन उन्हें कुछ लोगों ने याद दिलाया - 'अब सत्ता बदल चुकी है - समाज को भी बदलना होगा.' कलबुर्गी के विरुद्ध अभियान छेड़कर जान से मारने की धमकियां दे दी गईं. कर्नाटक में इस विवाद पर हंगामा घटता-बढ़ता रहा. कुछ साहित्य प्रेमी शुभचिंतकों ने कलबुर्गी को सांप्रदायिक हिंसक तत्वों से बचने के लिए सरकारी तंत्र से सुरक्षा लिए जाने का आग्रह किया. बताते हैं कि पहले कलबुर्गी इस सुझाव को स्वीकारने को तैयार नहीं थे, लेकिन परिजनों के आग्रह पर हाल ही में उन्होंने सरकारी सुरक्षा स्वीकारी. लेकिन इस ताम-झाम से ऊबकर उन्होंने कुछ दिनों पहले ही सुरक्षाकर्मियों को वापस लौटा दिया. आशंका यही जताई जा रही है कि कतिपय सांप्रदायिक तत्वों ने ही कलबुर्गी की उनके घर के दरवाजे पर ही गोली मारकर हत्या कर दी. इससे पहले महाराष्ट्र में कट्टरपंथियों ने नरेंद्र दाभोलकर की भी हत्या इसी तरह की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के कारण की थी.

इस मामले की जांच होती रहेगी. लेकिन संघ-भाजपा के नेताओं को अपने मंथन में यह सोचना होगा कि कुछ संगठनों के कुछ उग्रवादी लोगों और उनकी हिंसक गतिविधियों से समाज और राष्ट्र का कितना हित हो रहा है? वैसे एक वास्तविकता यह भी है कि सत्ता की चाशनी के कारण विषैले कीड़े-मकोड़ों की तरह ऐसे सैकड़ों लोग जुड़ रहे हैं जो संभवतः भारत की असली संस्कृति और संघ के संस्थापकों के विचारों से भी पूरी तरह परिचित नहीं हैं.

अंधविश्वास के विरुद्ध आवाज उठाने वालों की हत्या, धमकी, प्रतिबंध लोकतंत्र के साथ भारत की अस्मिता पर भी प्रहार है. सीमा पर आतंकवादी या आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादियों की तरह सांप्रदायिक तत्वों के हिंसक हमले भी राष्ट्रद्रोह से कम नहीं हैं. ■■

कमी के बावजूद क्यों नहीं बिक रहे मकान?

डॉ. जयंतीलाल भंडारी
प्रख्यात अर्थशास्त्री

यकीनन इस समय देश में मकानों की कमी और तैयार बिना बिके मकानों की बढ़ती संख्या की एक विसंगतिपूर्ण चिंताजनक तस्वीर उभरकर दिखाई दे रही है. इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि एक ओर देश में करीब 2 करोड़ मकानों की कमी है और करोड़ों लोग या तो जर्जर मकानों में गुजर-बसर कर रहे हैं या फिर झुग्गी-झोपड़ी में जीवन गुजार रहे हैं. जबकि दूसरी ओर करीब 1.1 करोड़ सजे-धजे मकान बिक नहीं पाने के कारण खाली पड़े हुए हैं. स्थिति यह है कि आवास क्षेत्र से संबंधित शेयर बाजार में सूचीबद्ध दिग्गज कंपनियों के पास मार्च 2015 के अंत तक करीब 70,000 करोड़ रुपए मूल्य के अनबिके मकान मौजूद थे. न केवल आवास क्षेत्र की बड़ी कंपनियां वरन् छोटी-छोटी कंपनियों की आवास निर्माण और आवास विक्रय संबंधी तस्वीर एकदम भयावह दिखाई दे रही है. आवास संबंधी राष्ट्रीय अध्ययन बता रहे हैं कि वर्ष 2015 में देश भर में मकानों की कीमत गिरेगी तथा कंपनियों के नकदी प्रवाह की स्थिति और बुरी हो जाएगी. यह स्थिति पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रही आवासीय कंपनियों को बैंक का ऋण चुका पाने में असमर्थ बना देगी.

देश में मकानों की मांग और अनबिके मकानों की स्थिति के बीच विसंगति कितनी चिंताजनक है, इसका शहर स्तर पर अनुमान हाल ही 2015 में प्रकाशित प्रॉपर्टी सलाहकार नाइट फ्रैंक की नवीनतम रिपोर्ट से लगाया जा सकता है. इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2015 की पहली छमाही में दिल्ली-एनसीआर में घरों की बिक्री में 50 प्रतिशत की गिरावट आई है. यह बिक्री 14,250 इकाई रही. इतना ही नहीं नए घरों की पेशकश 68 प्रतिशत घटकर 11,360 इकाई ही रह गई, जो पिछले साल की समान अवधि में 35,500 इकाई थी. दिल्ली-एनसीआर में बन चुकी, पर बिक नहीं पाई आवासीय इकाइयों की संख्या 1.90 लाख है. आवास क्षेत्र से संबंधित अनुभवी लोगों का कहना है कि यदि मौजूदा बिक्री को ध्यान में रखा जाए, तो बिल्डरों को इन मकानों को बेचने में पांच साल लगेंगे. चूंकि महंगे मकानों की अधिकांश खरीद निवेश के उद्देश्य से की गई है, न कि स्वयं उपयोग के लिए, इसलिए आवास क्षेत्र के हालात और खराब हो गए हैं. देश में आवास क्षेत्र में सुधार की संभावना इसलिए कम है क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्ती की चपेट में है और भारतीय अर्थव्यवस्था भी उससे अछूती नहीं है.

यकीनन जिंदगी की तीन अनिवार्य आवश्यकताओं रोटी, कपड़ा और मकान में से मकान की कमी इस समय देश के करोड़ों लोगों को दिन-प्रतिदिन के जीवन में तनावग्रस्त करते हुए दिखाई दे रही है. एक गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर हाउसिंग राइट्स एंड एविक्शन्स ने अपनी एक रिपोर्ट

करोड़ों लोग या तो जर्जर मकानों में गुजर-बसर कर रहे हैं या फिर झुग्गी-झोपड़ी में जीवन गुजार रहे हैं. जबकि दूसरी ओर करीब 1.1 करोड़ सजे-धजे मकान बिक नहीं पाने के कारण खाली पड़े हुए हैं.

में बताया है कि देश के करीब 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें जर्जर व बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चले मकानों और मलिन बस्तियों में गुजर-बसर करनी पड़ रही है. देश में लगातार तेजी से बढ़ती जनसंख्या आवास समस्या को और चुनौतीपूर्ण बनाते हुए दिखाई दे रही है. जुलाई 2015 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग की रिपोर्ट में बताया गया है कि जनसंख्या के मामले में 2022 में भारत चीन से आगे निकल जाएगा. चीन की आबादी अभी एक अरब 38 करोड़ है, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने भारत की जनसंख्या वर्तमान में एक अरब 31 करोड़ बताई है. रिपोर्ट का आकलन है कि सात वर्ष बाद दोनों देशों की आबादी तकरीबन एक अरब 40 करोड़ होगी. उसके बाद भारतीय जनसंख्या चीन से आगे निकल जाएगी. 2030 तक भारतीय जनसंख्या के डेढ़ अरब तक पहुंचने का अनुमान है. ऐसे में केंद्र सरकार के लिए यह जरूरी है कि वह तत्काल आवास क्षेत्र की विसंगति को दूर करने की डगर पर आगे बढ़े. ■■

आतंकवादियों के जिंदा पकड़े जाने के मायने

अवधेश कुमार
जाने-माने पत्रकार

एक महीने से कम समय में यह दूसरा अवसर है जब भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. पिछले पांच अगस्त को तो ग्रामीणों ने नावेद को उधमपुर में पकड़ा था और पुलिस के हवाले किया. हालांकि उसमें भी भूमिका सुरक्षा बलों की ही थी जिन्होंने उसके

सज्जाद 20 वर्ष का है और नावेद की उम्र भी लगभग इतनी ही है. यह अभी पता नहीं चला है कि दोनों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं.

साथी को मार दिया था तथा नावेद भागने को मजबूर हुआ था. हालांकि उस दिन जम्मू का क्षेत्र था लेकिन 27 अगस्त को तो घाटी का इलाका था. 20 वर्षीय सज्जाद उत्तरी कश्मीर के रफियाबाद (बारामूला) में पकड़ा गया. हमारे पास वह अपना क्या नाम बताता है उसे तत्काल स्वीकारने के अलावा कोई चारा नहीं होता. यही नावेद के मामले में हुआ और यही अब पकड़े गए आतंकवादी के मामले में हो रहा है. उसने जो नाम बताया उसके अनुसार वह सज्जाद अहमद उर्फ अबू उबैदुल्ला उर्फ फहदुल्ला उर्फ अब्दुल्ला है. पाकिस्तान अपनी आदत के अनुसार इसके अपने देश का निवासी होने से इनकार कर रहा है जैसा वह नावेद के मामले में करता रहा, जैसा वह मुंबई हमले में जिंदा पकड़े गए आतंकवादी के बारे में करता रहा. वह आगे भी ऐसा ही करेगा. किंतु उसके झूठ से सच बदल नहीं जाता. वैसे ऊपर से पाकिस्तान कुछ बोले अंदर से उसकी परेशानी आसानी से महसूस की जा सकती है. सच यह है कि पाकिस्तान में भारत विरोधी आतंकवाद के ढांचे इस समय काफी सशक्त हुए हैं, वहां से कम उम्र के आतंकवादियों को भ्रमित कर जम्मू-कश्मीर की सीमा में घुसपैठ कराया जाता है और वे अपनी वारदात को अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं.

सज्जाद 20 वर्ष का है और नावेद की उम्र भी लगभग इतनी ही है. यह अभी पता नहीं चला है कि दोनों के बीच कोई रिश्ता है या नहीं. नावेद ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को बताया था कि उसने अकेले घुसपैठ नहीं की थी. उसके साथ 18 आतंकवादियों ने घुसपैठ की थी. सबका प्रशिक्षण पाक अधिकृत कश्मीर में हुआ था. अगर एनआईए के सूत्रों की मानें तो उसके प्रशिक्षण में हाफिज सईद के पुत्र की भूमिका थी. धीरे-धीरे उससे पूछताछ में और विशेष जानकारी मिलेगी.

इनका पकड़ा जाना हमारे लिए इस मायने में बल प्रदान करने वाला है कि हम पाकिस्तान के पाखंड को नंगा करने में कुछ और सफल होंगे. पाकिस्तान में सरताज अजीज जैसे वरिष्ठ नेता यदि नाभिकीय हथियार की धौंस दे रहे हैं तो इसके पीछे यह भय भी है कि इस तरह अगर उनके देश के आतंकवादी पकड़े जाते रहे तो कहीं भारत कोई ऐसी कार्रवाई न कर दे जिसका मुकाबला करना कठिन हो जाए. ■■

नजर के पार

सम्मान

दो शिक्षिकाएं अपने-अपने विद्यालय में आयोजित विशेष समारोह के बाद घर लौट रही थीं. रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई. दोनों के हाथों में बड़ा-सा थैला था. पहली शिक्षिका ने दूसरी से पूछा, ''अरे तुम्हारे इस बड़े से थैले में क्या है?''

लघुकथा

गोविंद भारद्वाज

''दूसरी से कहा, आज मुझे स्कूल के बच्चों ने बड़े अच्छे-अच्छे गिफ्ट्स दिए हैं, इसमें वे ही हैं....''

''और माला नहीं पहनाई क्या?'' पहली ने पूछा.

''पहनाई थी न ....ढेरों पहनाई थी... मगर कौन बोझ खींचता मालाओं का... उन्हें तो वहीं फेंक आई.'' दूसरी शिक्षिका ने जवाब दिया. फिर पहली से पूछा ''तुम्हारे गिफ्ट्स कहां हैं आज के दिन तो सभी को गिफ्ट्स मिलते हैं चलो दिखाओ.... अपने थैले को.... अरे इसमें तो फूलों की मालाएं हैं.''

पहली ने जवाब दिया, ''हां, फूलों की मालाएं हैं. मैं अपने उपहार गरीब बच्चों को बांट आई और जो सम्मान में मालाएं पहनाई गई थीं वो सारी ले आई हूं. ये बोझ ही असली सम्मान है मेरे लिए.'' ■■

चीन के संकट से भारत के लिए अवसर

अश्विनी महाजन
वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही में चीन द्वारा अपनी करेंसी का 4.4 प्रतिशत से भी ज्यादा अवमूल्यन करने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों और विदेशी मुद्रा बाजारों में भारी खलबली मच गई. युआन के अवमूल्यन की प्रतिस्पर्द्धा में दुनिया भर की करेंसियों में डॉलर के मुकाबले भारी अवमूल्यन हुआ ताकि युआन के अवमूल्यन का उन पर कोई असर न हो. इतिहास गवाह है कि मुद्रा के प्रतिस्पर्द्धी अवमूल्यन का कभी किसी देश को लाभ नहीं हुआ है. 1930 के दशक की वैश्विक मंदी के दौरान भी इसी प्रतिस्पर्द्धी अवमूल्यन ने अर्थव्यवस्थाओं को चौपट किया था.

पिछले दो से ज्यादा दशकों में चीनी अर्थव्यवस्था में तेजी से ग्रोथ हो रही थी, जो कई बार 15 प्रतिशत से भी ज्यादा पहुंच गई. मोबाइल फोन और अन्य टेलीकॉम उपकरणों, खिलौनों, बिजली के साजो-समान, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से लेकर बड़ी और छोटी मशीनों सभी प्रकार की वस्तुओं का चीन भारी मात्रा में निर्यात करने लगा और भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोप के मुल्कों के बाजारों में भी चीनी माल का आधिपत्य हो गया. चीन में चीनी कंपनियां ही नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी वहां जाकर उत्पादन करने लगीं. भारत से भी बड़ी मात्रा में उद्योगपतियों ने पलायन कर चीन में जाकर अड्डा जमा लिया और चीन दुनिया का 'मैन्युफैक्चरिंग हब' बन गया.

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन संकटों में आ गया है. उसका पहला संकट है वहां भारी मुद्रा स्फीति. चीन में कीमतें बढ़ने लगी थीं, जिसके कारण अब मजदूरी दर भी बढ़ गई थी. सामान्य मजदूर की न्यूनतम मजदूरी 960 युआन

प्रतिमाह से बढ़कर 2015 में 1820 युआन तक पहुंच गई. दूसरे, चीन की प्रांतीय सरकारें जो चीनी उत्पाद को सस्ता रखने के लिए सब्सिडी देती थीं, उसके कारण चीन में राजकोषीय घाटा सीमाएं पार कर चुका था. अब सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं रही. तीसरे, अमेरिका और यूरोप में आई मंदी के चलते चीन से इन देशों को निर्यात घटने लगे और यही नहीं चीनी माल के पहले से महंगा होने के कारण अब दूसरे मुल्कों ने भी अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी. चीन की मंदी का चौथा महत्वपूर्ण कारण था, वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश का घटना. चीन ने पिछले दो दशकों के दौरान रेल, सड़क, बिजली समेत तमाम प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया है, लेकिन अब उस निवेश की गति बहुत धीमी हो गई, जिसके चलते चीन में ग्रोथ घटने लगी.

चीन की अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट के जरिए हम अपने उद्योगों को और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रेरित कर सकते हैं. इसके लिए सरकार के पास उद्यमियों के लिए निवेश और उत्पादन अनुकूल वातावरण देने का वादा भी है. साथ ही हमारी सरकार की ओर से निवेशकों को 'मेक इन इंडिया' के जरिए निवेश का आमंत्रण भी दिया जा रहा है. आज हम मंगल ग्रह की कक्षा तक अपने उपग्रह को भेज सकते हैं, वह भी बहुत कम लागत में. दूरस्थ मार करने वाले मिसाइल ही नहीं, परम कम्प्यूटर और एटम बम तक बना सकते हैं, तो उद्योगों के विकास में क्या कठिनाई है. संकेत स्पष्ट है कि हम बाजार की उठापटक को भी अपने लिए अवसरों में तब्दील कर सकते हैं. ■■

तोल बोल

पाकिस्तान को अपनी ताकत और हथियारों को लेकर कुछ गलतफहमी थी. हमने उसे सही जवाब दिया. कश्मीर को पाकिस्तान ताकत के बल पर हमसे कभी छीन नहीं सकता. ■ **मनोहर पार्रिकर**, रक्षा मंत्री

''मेरा मानना है कि नाना पाटेकर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ईमानदार व्यक्ति हैं. मैं उन्हें कभी उनके गुस्से के लिए दोष नहीं दूंगा.
■ **जॉन अब्राहम**, फिल्म अभिनेता

gñWmnH$ gnmXH$: ñd. Odmhabmb XS>m
M`a_Z, E{S>Q>a{`b ~moS>© : {dO` XS>m
E{S>Q>a-BZ-Mr\$: amOoÐ XS>m
gnmXH : {dH$mg {_lm
nr. Am. ~r. H$mZZ H$ AZgma gnU gnmXH$s` Xm{`Ëd H$ {bE {OåÓ_Xma.

© लोकमत समाचार _ àH$m{eV g^r g_Jr H$ gdm©{YH$ma bmoH$_V ... bmoH$_V _r{S>`m àm. {b. H$ {bE _w{ÐV Ed àH$m{eV बालाजी मुले Ûmam bmoH$_V _r{S>`m àm. {b., {~bm° H$. 192, 207, 208 E_. AmB. S>r. gr. B§S>{ñQ´>`b E[a`m, ~Or~mar, ZmJnw_ {dV Ed bmoH$_V ^dZ n. Odmhabmb Zhê _mJ, ZmJnw_ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmBZ) \¡Šg : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 2 सितंबर

करीब दो सदियों से भारत पर काबिज ब्रितानी हुकूमत से भारतवासियों को सत्ता सौंपने के लिए साल 1946 में आज ही के दिन अंतरिम सरकार का गठन हुआ था. यूं तो माउंटबेटन इस सरकार के मुखिया थे और भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी, लेकिन बाकी सभी अधिकार इस सरकार में शामिल भारतीयों के पास थे. जवाहर लाल नेहरू इस सरकार में उपराष्ट्रपति थे जिनके पास प्रधानमंत्री के सभी अधिकार समाहित थे. सरदार वल्लभभाई पटेल इस सरकार में महत्वपूर्ण समझे जाने वाले आंतरिक सुरक्षा और सूचना प्रसारण मंत्रालयों के प्रभारी थे. मुस्लिम लीग की तरफ से इस अंतरिम सरकार में लियाकत अली थे जिनके पास देश के वित्त मंत्रालय का प्रभार था. ■■

- 1775-पहले अमेरिकी युद्ध पोत हाना का जनरल जॉर्ज वाशिंगटन ने जलावतरण किया.
- 1898-मशीनगन का युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया गया.
- 1945-द्वितीय विश्व युद्ध छह साल एक दिन चलने के बाद समाप्त हो गया.
- 1945-हो ची मिन्ह ने वियतनाम को स्वतंत्र घोषित किया.
- 1992-अमेरिका और रूस अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए संयुक्त उपक्रम बनाने पर सहमत हुए.
- 1998-चालकरहित विमान 'निशांत' को सफलतापूर्वक उड़ाया गया.

पाठकों के पत्र

विचारोत्तेजक लेख

गुजरात में पटेल समुदाय की आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन की पृष्ठभूमि पर विगत 31 अगस्त को लोकमत समाचार के संपादकीय पेज पर श्री विजय दर्डा का लेख विचारोत्तेजक लगा कि यदि हर समुदाय आरक्षण की मांग करने लगेगा तो इससे किस तरह भारत का विकास बाधित होगा. विप्रो के चेयरमैन अजीज प्रेमजी ने प्रतिकूल आरक्षण नीति पर फेसबुक पर दिलचस्प प्रतिक्रिया लिखी है और बताया है कि यदि सरकार द्वारा इसे दबाव के तहत कार्यान्वित किया जाता है तो क्या होगा. उम्मीद है कि हम सभी भारतीय आरक्षण की मांग के खिलाफ खड़े होंगे और एकजुट होकर भारत का निर्माण करेंगे, कई अन्य देशों की तरह, जहां जाति व्यवस्था बहुत पहले खत्म हो चुकी है.
■ **जिनेंद्र मुणोत**, पुणे

हर तरह का प्रदूषण मिटाएं

सामाजिक-सांस्कृतिक ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण का असर हमारे मन-मस्तिष्क पर होता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी असर डालता है तथा कई बीमारियां पैदा होती हैं. इसलिए हमें हर स्तर पर ध्यान देने की जरूरत है. ■ **डॉ. सुरेश खलाले**, नागपुर

आप भी अपने पत्र हमें lsedit.ngp@lokmat.com पर मेल कर सकते हैं या डाक पते पर भेज सकते हैं.

खुशी का रहस्य

हास्य

नसरुद्दीन की शादी होने के कुछ ही दिन बाद उनसे उनका मित्र मिला.

मित्र ने पूछा, ''कैसी चल रही है?''

नसरुद्दीन ने कहा, ''ठीक चल रही है.''

मित्र ने पूछा, ''दोनों खुश हो या नहीं?''

''खुश हैं. मेरी बीवी मुझे रोज बर्तन उठाकर मारती है.''

मित्र ने बेसब्री से पूछा, ''फिर दोनों खुश कैसे हो?''

नसरुद्दीन ने कहा, ''जब उसका निशाना सही लगता है तब वह खुश होती है, और जब निशाना चूक जाता है तो मैं खुश होता हूं.''

इसी तरह नसरुद्दीन एक बार नेत्र-चिकित्सक से अपनी परीक्षा करवा रहे थे. उन्होंने पूछा, '' डॉक्टर साहब - चश्मा लगाकर मैं पढ़ भी सकूंगा?''

हां, हां, क्यों नहीं? नेत्र चिकित्सक ने फौरन जवाब दिया.

ओह फिर तो बहुत अच्छा रहेगा. अब तक तो मुझे पढ़ना भी नहीं आता था. नसरुद्दीन ने कहा. ■■